इकनॉमिक टाइम्स

Publication: The Economic Times - Hindi , Agency: Bureau, Edition: Delhi, Page No: 03, Location: Middle-Left, Height: 9, Width: 28, Size(sq.cms): 252

सरकार ने प्रायरिटी स्कीमों पर ली जनता की राय

BSNL के 800 कॉल एजेंट्स ने प्रतिक्रिया के लिए 10 दिन में 8 लाख कॉल्स किए

अमन शर्मा नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने हाल ही में अपनी कुछ अहम स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इसके लिए 10 दिन में 8 लाख कॉल्स की गईं, चंद सवाल पूछे गए और सुधार के लिए सुझाव मांगे गए। यह काम लगभग 800 भारत संचार निगम लिमिटेड के कॉल एजेंट्स ने किया। इसका मकसद उन जिलों की पहचान करना था जिनका परफॉर्मेंस 4 अहम स्कीमों के कार्यान्वयन में सबसे अच्छा रहा है।

जिन स्कीमों की समीक्षा की गई है वे हैं - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), स्वच्छ भारत (ग्रामीण), स्वच्छ विद्यालय और सॉयल हेल्थ कार्ड। पब्लिक के फीडबैक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे पर सर्वश्रेष्ठ जिलों के अवार्ड का ऐलान करेंगे। अवॉर्ड्स में 10 लाख रुपये का इनाम होगा। पहली बार ऐसा होगा जब प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे।

सीनियर सरकारी ऑफिसर्स ने इनकॉमिक टाइम्स को बताया कि पीएम ने फरवरी की शुरुआत में आइडिया दिया था कि किन जिलों में प्राथमिकता वाली योजनाओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से लागू किया गया है, यह तय करने के लिए लाभार्थियों से फीडबैक मांगा जाना चाहिए। चारों योजनाओं पर नजर रखने वाले डिपार्टमेंट्स ने सर्वश्रेष्ठ जिलों की शुरुआती शॉर्ट लिस्ट के साथ ऑफिशियल डेटा सौंपे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा ने पब्लिक से बातचीत करने के अभियान की जिम्मेदारी उठाई, जिसको पीएम के सुझाव के तीन हफ्तों के भीतर शुरू कर दिया गया। फरवरी के अंतिम और मार्च के पहले हफ्ते में शॉर्ट लिस्ट किए गए जिलों में पब्लिक से पूछने के लिए हर स्कीम पर 8 से 10 सवाल तैयार किए गए थे।

कैबिनेट सेक्रेटेरियट के एक सीनियर ऑफिसर ने पहचान जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर इकनॉमिक टाइम्स से कहा, 'यह इतने कम समय में पब्लिक का फीडबैक लेने का केंद्र या राज्य सरकार का सबसे बड़ा अभियान होगा। लाभार्थियों के सुझाए सुधार अपने आप में स्कीमों को बेहतर बनाने के लिए सबसे अहम इनपुट हैं।' फीडबैक अवार्ड विजेता जिला चुनने में एक प्रभावी इनपुट होगा। इनके लिए जिलों को इवैल्यूएशन और एक्सपर्ट कमेटी के जरिए कई फिल्टरिंग प्रोसेस गुजारा जाएगा। अवॉर्ड्स के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को बराबरी का मौका देने के लिए कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 10-10 लाख रुपये के 10 अवॉर्ड होंगे। पब्लिक से पूछे गए सवाल प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी और भ्रष्टाचारमुक्त कार्यान्वयन से संबंधित थे। काम में दल बनाकर काम करने की भावना के प्रदर्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ऑफिसर को अवॉर्ड दिए जाएंगे। जन धन योजना के लिए खासतौर पर महिलाओं के जीरो बैलेंस एकाउंट्स में कमी, स्कीमों को मुश्किल हालात वाले इलाकों में लागू करने और आधार सीडिंग वगैरह से जुड़े सवाल पूछे गए थे।